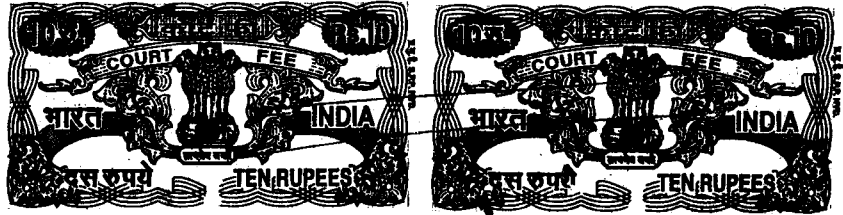


103

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालिथर ॥ सर्किट कोर्ट रीवा ॥ जिला
रीवा म.प्र.



Rs. 20/-

224
27-6-15

निगरानी 2406-IT-15

- 1- बैजनाथ पिता स्व. महावीर पटेल
- 2- रामलाल पटेल | पुत्रगण स्व. श्री रामस्य पटेल
- 3- श्यामलाल पटेल ।

सभी निवासी ग्रामजल्दर तहसील जिला रीवा म.प्र.

.... निगरानी कर्ता गण

वनाम

- 1- रामप्रसाद पिता अब्दुलशरण द्विवेदी
- 2- रामचन्द्र द्विवेदी पिता श्री अब्दुलशरण द्विवेदी
- 3- कृष्णचन्द्र पिता अब्दुलशरण द्विवेदी

सभी निवासी ग्राम बांधी तहसील जिला रीवा म.प्र.

... गैर निगरानी कर्ता गण प्रत्या र्धी गण

श्री. मि. न. प्र. वा. ठ. क. ... एड
द्वारा आज दिनांक 27-6-15
प्रस्तुत किया गया।

सेर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण/निगरानी विरुद्ध म्याद अधिनियम
1963 ई. की धा रा 5 के आवेदन पत्र पर
पारित आदेश दिनांक 27-4-2015 प्र. क्र. 101/
अ6/2013-14 द्वारा पारित अधिनस्थ न्याया
श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील
गुड जिला रीवा म.प्र.

अंतर्गत धा रा 50 म.प्र. भू. रा. सं. 1959 ई.

क्रमांक.....
रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा आज
दिनांक..... को प्राप्त

करकें ऑफिसियल
राजस्व मण्डल ग्वालिथर

पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

✓

१११ यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा म्याद आवेदन पत्र पर पारित आदेश दिनांक 27-4-2015 प्र. क्र. 101/अ6/2013-14 विधि प्रकृया के विरुद्ध सर्व अधिकारी रता रहित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

१२१ यह कि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुड के समक्ष


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2406-दो/2015

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-5-2017	<p>आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुड जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 101/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27-4-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 27-4-2015 को अपीलांत को वादग्रस्त भूमि के हितबद्ध पक्षकार मानते हुये म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन आदेश से मात्र अपील को समय-सीमा में माना है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दायित्व रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">  (एस0एस0 अली) सदस्य </p>	